



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2018/चैत्र 27, 1940

No. 159]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2018/CHAITRA 27, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 27 मार्च, 2018

सं. टीएमपी/73/2017-वीओसीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, मै. पीएसए सिकाल टर्मिनल लि. द्वारा उपभोग की गई बिजली के लिए बिजली प्रभागों पर उपरिव्यय प्रभागों की वसूली हेतु वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/73/2017-वीओसीपीटी

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी)

.....

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मार्च, 2018 के 19वें दिन पारित)

यह मामला मै. पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल लि. (पीएसएसआईसीएल) द्वारा उपभोग की गई बिजली के लिए बिजली प्रभागों पर उपरिव्यय प्रभागों की वसूली के संबंध में वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 05 सितम्बर 2017 से संबंधित है।

2.1. वीओसीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 05 सितम्बर 2017 में कही गई बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i). वीओसीपीटी ने पहले पत्तन उपयोक्ताओं, संविदाकारों और पीएसएसआईसीएल के मामले में बिजली की आपूर्ति के मामले में रु. 1.15/इकाई की दर से उपरिव्यय प्रभागों की वसूली के लिए प्रस्ताव किया था।

तथापि, प्राधिकरण ने पीएसएसआईसीएल के सिवाय पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों से बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिचय्य व्ययों की वसूली के लिए आदेश सं. टीएमपी/22/2006-टीपीटी दिनांक 14 जुलाई 2008 द्वारा बिजली की रु. 1.15 प्रति इकाई अनुमोदित की थी। प्राधिकरण ने परिचालक के साथ अनुबंध द्वारा प्राधिकृत अस्पष्ट पुष्टि उद्धरित करते हुए VII बर्थ कंटेनर टर्मिनल में बिजली के उपयोग के लिए पीएसएसआईसीएल से रु. 1.15/इकाई की दर से उक्त प्रभारों की वसूली करने के लिए पत्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया था।

- (ii). इस संबंध में, मै. पीएसएसआईसीएल को उपरिचय्य प्रभारों की अनुप्रयोज्यता करने के लिए एक बार दोबारा उपरिचय्य प्रभारों की वसूली के मुद्दे को उठाने के लिए पत्तन के सतर्कता सुझाव पर विचार करते हुए भी, पत्तन के विधिक प्रकोष्ठ से कानूनी राय प्राप्त की गई है। 03 अगस्त 2017 को प्राप्त कानूनी राय की प्रति वीओसीपीटी द्वारा भेजी गई है जिसे सुलभ संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:—

*“क्या लाइसेंस करार के खंड 6.1.8 के अनुसार पत्तन न्यास मै. पीएसएसआईसीएल टर्मिनल लि. से उपरिचय्य प्रभारों की वसूली करने के लिए हकदार है, इस मामले में इस प्रश्न पर निर्णय किया जाना है। लाइसेंस करार का खंड 6.1.8. बिजली तथा पानी आपूर्ति और मै. पीएसएसआईसीएल टर्मिनल लि. के लाइसेंसशुदा परिसर को आपूर्ति की गई बिजली के लिए प्रभारों की वसूली से संबंधित है।*

*उपर्युक्त खंड के अनुसार, लाइसेंसधारी पर वसूल किए गए बिजली प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार होंगे। वित्त और अभियांत्रिक बिजली इंजीनियरिंग विभाग का यह दावा है कि उपरिचय्य प्रभार पत्तन में निजी टर्मिनल परिचालकों सहित सभी पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों से वसूल किए जाते हैं, उनके साथ किए गए करारों के अनुसार है। चूंकि, उपरिचय्य प्रभारों की वसूली के संबंध में, मै. पीएसएसआईसीएल टर्मिनल लि. के साथ किए गए लाइसेंस करार में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पत्तन को उनसे उपरिचय्य प्रभारों की वसूली करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है।*

*सामान्य संशोधन आदेश दिनांक 11 दिसम्बर 2011 में, पत्तन से उपयोक्ताओं/संविदाकारों तक बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिचय्य प्रभारों की वसूली करने के लिए उपभोग की गई बिजली की 1.15 प्रति इकाई की दर से निर्धारित मौजूदा प्रशुल्क निर्धारित किया गया है, इसे संशोधित दरमान में बनाये रखा गया था। टीएनईबी संप्रेषण जिसने ट्रांसफार्मर हानि, एमडी प्रभारों आदि के रूप में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पट्टाधारी से उपरिचय्य प्रभारों की वसूली करने के लिए पत्तन को अनापत्ति संप्रेषित की थी, उल्लेख किया गया है कि अब तक उपरिचय्य प्रभार टीएनईबी के निबंधन एवं शर्तों के 31.03 (1) के प्रावधानों का विधिवत् अनुपातन करते हुए वसूल किए गए हैं अर्थात् संग्रहण 'न लाभ न हानि आधार' पर किया गया है। लाइसेंस करार के खंड 6.1.8. के अनुसार, पत्तन टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार लाइसेंसधारी को प्रभारों की वसूली करने का हकदार है। वैसे टीएनईबी की दरों की अनुसूची में टीएनईबी के निबंधन एवं शर्तों के 31.03 (1) के प्रावधानों के अनुसार उपरिचय्य प्रभार भी शामिल होंगे, यदि संग्रहण 'न लाभ न हानि आधार' पर किया गया हो।*

*यहां तक कि उपरिचय्य प्रभारों के संग्रहण के लिए लाइसेंस करार के खंड 6.1.8 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लाइसेंसधारी पर वसूल किए गए प्रभार शब्द टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार होंगे जिसमें उपरिचय्य प्रभारों का संग्रहण भी शामिल होगा। इसे प्रभारों के अतिरिक्त संग्रहण के रूप में नहीं माना जाएगा जैसा पूर्व कानूनी राय में पहले बताया गया है।”*

- 2.2. उपर्युक्त के मद्देनजर, वीओसीपीटी ने इस प्राधिकरण से अध्याय V के मान 5.21 द्वारा मौजूदा दरमान के मामले में भी पीएसएसआईसीएल पर उपरिचय्य प्रभार लागू करने के लिए पत्तन के मौजूदा निवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

3. मामले का संक्षिप्त इतिहास नीचे दिया गया है:

- (i). वीओसीपीटी ने पीएसएसआईसीएल सहित सभी उपयोक्ताओं के लिए बिजली प्रभारों के मामले में उपरिचय्य प्रभारों की वसूली करने के लिए लेवी निर्धारित करने हेतु अनुरोध करते हुए 2003 में इस प्राधिकरण का रुख किया था।
- (ii). वीओसीपीटी ने तब कानूनी सलाहकार श्री बी. भारत भूषण से प्राप्त कानूनी राय की प्रति अग्रेषित की गई थी जिसके बारे में इस प्राधिकरण द्वारा पादित आदेश सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी दिनांक 4 मई 2004 के पैरा 6.2 में बताया गया है। इस मामले की कार्यवाही के दौरान, पीएसएसआईसीएल ने प्रस्तावित लेवी का विरोध किया था।
- (iii). वीओसीपीटी द्वारा कानूनी सलाहकार श्री बी. भारत भूषण से यथा प्राप्त की गई वीओसीपीटी द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2004 को समाहार पैरा में दी गई कानूनी राय निम्नवत् है:

*“मैं, अतः, सुझाव दूंगा कि यह प्रस्ताव समानुपातिक वृद्धि के साथ, मै. पीएसएसआईसीएल लि. के सिवाय जोकि आपके साथ हुए करार द्वारा संरक्षित है, सभी उपयोक्ताओं पर लागू किया जा सकता है। वृद्धि के प्रतिशत के बारे में बोलते हुए, मेरा अनुमान है, यह उचित अनुपात में होनी चाहिए।”*

इस प्रकार, 2004 में वीओसीपीटी द्वारा तब अग्रेषित कानूनी राय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरिचय्य प्रभार मै. पीएसएसआईसीएल लि. के सिवाय जोकि वीओसीपीटी के साथ उनके करार द्वारा संरक्षित है, सभी उपयोक्ताओं पर लागू होंगे।

- (iv). इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 4 मई 2004 द्वारा वीओसीपीटी के उस प्रस्ताव को खारिज किया था जिसमें उक्त आदेश में उल्लिखित कारणों से बिजली आपूर्ति के लिए प्रासंगिक उपरिचय्य व्ययों को कवर करने के लिए नई लेवी शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।
- (v). (क). तत्पश्चात्, वीओसीपीटी ने वर्ष 2006 में बिजली प्रभारों के मामले में उपरिचय्य प्रभारों की वसूली करने के लिए लेवी निर्धारित करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्राधिकरण ने बिजली की आपूर्ति के मामले में उपरिचय्य प्रभारों की वसूली करने के लिए

वीओसीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों द्वारा उपभोग की गई बिजली की रु. 1.15 प्रति इकाई की लेवी अपने आदेश सं. टीएमपी/22/2006-टीपीटी दिनांक 14 जुलाई 2008 द्वारा अनुमोदित की थी।

- (ख). पीएसए सिकाल के संबंध में, आदेश दिनांक 14 जुलाई 2008 का पैरा 9(viii) जो वीओसीपीटी द्वारा तत्समय प्रेषित कानूनी राय पर आधारित था, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*“टीपीटी ने पीएसए सिकाल को बिजली की आपूर्ति को भी प्रस्तावित वसूली के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया था। पीएसए सिकाल ने यह दावा करते हुए प्रस्तावित लेवी को चुनौती दी थी कि उसे बीओटी करार के अनुसार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के आधार पर प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।*

*बीओटी करार का खंड 6.1.8 बिजली और पानी आपूर्ति व्यवस्था को विनियमित करता है। प्रासंगिक खंड स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करता है कि लाइसेंसधारी पर प्रभारित प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दर के अनुसार होंगे। टीपीटी द्वारा पहले प्राप्त कानूनी राय भी पीएसए सिकाल द्वारा बनाये रखी गई स्थिति का समर्थन करती है।*

*तथापि, टीपीटी ने टीएनईबी के पत्र का उल्लेख किया है जिसमें ट्रांसफार्मर हानि, एमडी प्रभारों आदि के रूप में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पट्टाधारी से उपरिव्यय प्रभारों की वसूली करने के लिए पत्तन को अनापत्ति संप्रेषित की थी, उल्लेख किया गया है कि अब तक उपरिव्यय प्रभार टीएनईबी के निबंधन एवं शर्तों के 31.03 (1) के प्रावधानों का विधिवत् अनुपातन करते हुए वसूल किए गए हैं अर्थात् संग्रहण ‘न लाभ न हानि आधार’ पर किया गया है। टीएनईबी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सामान्यतः टीपीटी को उपरिव्यय प्रभारों की वसूली करने की अनुमति देता है परन्तु यह बीओटी करार में दिये गए प्रावधानों की जांच करने के बाद पीएसए सिकाल के विशेष मामले में दिया गया दिखाई नहीं देता है।*

*टीपीटी यह स्पष्ट रूप से पुष्टि करने में असमर्थ रहा है कि यह पीएसएसिकाल से बिजली के वितरण के लिए उपरिव्यय की वसूली करने के लिए बीओटी करार के अधीन प्राधिकृत नहीं है। अतः पीएसए सिकाल से उपरिव्यय प्रभारों की वसूली करने का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।*

*संयोगवश, टीपीटी ने भी बाद में पीएसए सिकाल के मामले में बिजली पर उपरिव्यय प्रभारों की वसूली के अपने प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लंबित करते हुए इसके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए तैयार संशोधित लागत विवरण में अधिशेष/घाटा स्थिति का अनुमान लगाने के लिए पीएसए सिकाल से संबंधित व्यय को शामिल किया था।”*

- (vi). तत्पश्चात्, इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएमपी/9/2010-टीपीटी दिनांक 11 अक्टूबर 2011 द्वारा वीओसीपीटी के दरमान का सामान्य संशोधन अनुमोदित करते समय, पीएसएसिकाल के सिवाय पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों से बिजली की आपूर्ति के लिए 14 जुलाई 2008 आदेश में अनुमोदित रु. 1.15 प्रति इकाई की दर से तत्समय मौजूदा लेवी की वसूली की अनुमति दी थी जैसाकि 11 अक्टूबर 2011 आदेश के पैरा 17(xLv) में बताया गया है।
- (vii). प्रशुल्क नीति 2015 के अधीन वीओसीपीटी के दरमान के अनुवर्ती सामान्य संशोधन को आदेश सं. टीएमपी/29/2016-वीओसीपीटी दिनांक 17 सितम्बर 2016 द्वारा अनुमोदित करते समय, इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित पीएसएसिकाल के सिवाय पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकार से बिजली की आपूर्ति के लिए रु. 1.47 प्रति इकाई की दर से पत्तन द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिव्यय व्ययों की वसूली अनुमोदित की थी।

4.1. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि वीओसीपीटी ने अपने पत्र सं. एफआईएन/ऑफसीजे-एसओआर-जेन-IV-15-4090 दिनांक 18/19 दिसम्बर 2015 द्वारा मै. पीएसए सिकाल टर्मिनल लि. द्वारा उपभोग की गई बिजली पर रु. 1.15 प्रति इकाई की दर से उपरिव्यय प्रभारों की वसूली पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के आधार पर मुद्दे की जांच करने का अनुरोध किया गया था और लेखापरीक्षा अभियुक्त के निपटान के लिए इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएमपी/9/2010-टीपीटी दिनांक 11 अक्टूबर 2011 को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था।

4.2. इस संबंध में, हमारे पत्र दिनांक 7 जनवरी 2016 वीओसीपीटी को संप्रेषित किया गया था कि पीएसए सिकाल के लिए लेवी नहीं अनुमोदित करने का जुलाई 2008 आदेश में इस प्राधिकरण का निर्णय अक्टूबर 2011 के प्रशुल्क आदेश में वापिस नहीं लिया गया है। इसलिए, पीएसए सिकाल से उपरिव्यय प्रभारों की वसूली नहीं करने की वीओसीपीटी की कार्यवाई अक्टूबर 2011 में इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार पाई गई है। वीओसीपीटी ने उक्त आदेश में सुविचारित अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में किसी त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है। इसलिए, वीओसीपीटी द्वारा अक्टूबर 2011 आदेश में संशोधन किए जाने की मांग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

5. वीओसीपीटी ने अब उपर्युक्त पैरा 2.1 में यथा उल्लिखित वीओसीपीटी के विधि प्रकोष्ठ की कानूनी राय उद्धरित करते हुए, इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे पर पत्तन के मौजूदा निवेदन पर विचार किया जाए और अध्याय V के मान 5.21 द्वारा मौजूदा दरमान के मामले में भी पीएसएसिकाल से उपरिव्यय प्रभारों के संग्रहण के लिए अनुमोदन की मांग की है।

6. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीओसीपीटी के प्रस्ताव की प्रति मै. पीएसए सिकाल टर्मिनल लि. और तमिलनाडु बिजली बोर्ड को हमारे पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2017 द्वारा उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। पीएसएसिकाल से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वीओसीपीटी को अग्रेषित की गई थीं। वीओसीपीटी ने उसपर कोई टिप्पणियां नहीं भेजी थीं।

7. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 7 दिसम्बर 2017 को वीओसीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। वीओसीपीटी ने अपने प्रस्ताव की संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुति पेश की थी। संयुक्त सुनवाई में, वीओसीपीटी, पीएसएसिकाल और टीएनईबी ने अपने निवेदन रखे थे।

8. संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, हमारे पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2017 और अनुवर्ती अनुस्मारक दिनांक 10 जनवरी 2018 द्वारा वीओसीपीटी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था:-

- (i). हमारे पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2017 द्वारा वीओसीपीटी का ध्यान आकर्षित किया गया था कि इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी के पत्र दिनांक 25 मार्च 2004 द्वारा 2004 में वीओसीपीटी द्वारा अग्रेषित कानूनी सलाहकार श्री बी. भारत भूषण की उस समय की कानूनी राय के आधार पर एक आदेश सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी दिनांक 4 मई 2004 पारित किया था। वीओसीपीटी द्वारा उस समय अग्रेषित कानूनी राय जिसे आदेश दिनांक 4 मई 2004 के पैरा 6.2 में भी पुनः प्रस्तुत किया गया है, में उल्लिखित किया गया है कि उपरिख्य प्रभार की वसूली के लिए वीओसीपीटी का प्रस्ताव पीएसएसिकाल जो पत्तन के साथ उनके द्वारा किए गए करार द्वारा संरक्षित है, के सिवाय सभी उपयोगिताओं पर लागू किया जा सकता है। अब, वीओसीपीटी ने पत्तन के विधि प्रकोष्ठ द्वारा दी गई कानूनी राय के आधार पर इस प्राधिकरण का रुख किया है। पत्तन द्वारा अपने विधि प्रकोष्ठ से 2004 और अब भेजी गई कानून राय में विरोधाभास है। इसलिए, वीओसीपीटी से मामले की बारीकी से जांच करने और अपनी टिप्पणी तत्काल भेजने का अनुरोध किया गया था। वीओसीपीटी ने संयुक्त सुनवाई में कहा था कि वह इस मामले में एजी की कानूनी राय प्राप्त करेगा। पत्तन से इसकी एक प्रति इस प्राधिकरण को भेजने का अनुरोध किया गया था।
- (ii). रु. 1.47/टन की दर से बिजली की आपूर्ति हेतु उपरिख्य व्ययों की वसूली हेतु मौजूदा संशोधित दर का निर्धारण एआरआर मॉडल के अधीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा जारी 2015 के प्रशुल्क नीति दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए पत्तन के दरमान के सामान्य संशोधन के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त आदेश में, पत्तन द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिख्य व्ययों की वसूली के लिए प्रभारों सहित विभिन्न कार्यों, पोत तथा विविध सेवाओं के लिए वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित दरें इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई थीं।

संयुक्त सुनवाई में, एक बिन्दु उठा था कि क्या ट्रांसमिशन नुकसान सहित बिजली के वितरण हेतु सम्पूर्ण परिख्य प्रभार पत्तन द्वारा वसूल किया जा रहा है। संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, वीओसीपीटी से यह जांच करने के लिए लागत विश्लेषण करने का अनुरोध किया गया था कि क्या बिजली के वितरण के लिए पत्तन द्वारा प्रोद्भूत सम्पूर्ण उपरिख्य प्रभार वीओसीपीटी द्वारा दरमान के उक्त सामान्य संशोधन में प्रस्तावित और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रु. 1.47 प्रति इकाई की मौजूदा दर वीओसीपीटी द्वारा वसूल की जाती है और इसे इस प्राधिकरण को भेजें।

9.1. उपर्युक्त पैरा 8 (i) में दिये गए संयुक्त सुनवाई में निर्णीत कार्रवाई के बिन्दु के संदर्भ में, वीओसीपीटी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एसजी) द्वारा वीओसीपीटी द्वारा दी गई कानूनी राय दिनांक 17 जनवरी 2018 की प्रति अपने पत्र दिनांक 1 फरवरी 2018 द्वारा भेजी थी। एसजी की राय को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“4. निर्माण से संबंधित करार का अनुच्छेद 5 और खंड 5.6 निम्नवत् पढ़ें:-

“5.6 निर्माण बिजली और पानी

लाइसेंसदाता निर्माण प्रयोजनों के लिए बिजली आपूर्ति करेगा, जैसाकि तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा, लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान सहित निबंधन एवं शर्तों के अधीन, लाइसेंसदाता को अनुच्छेद 6.1.8 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाई गई है।”

5. लाइसेंसधारी के दायित्वों से संबंधित अनुच्छेद 6 के अधीन खंड 6.1 और लाइसेंसदाता के दायित्वों से संबंधित खंड 6.2/ पैरा 6.2.1(viii) निम्नवत् पढ़ें:-

“6.2.1 (viii) अनुच्छेद 6.1.8 के अनुसार समय-समय पर लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित की जाने वाली दरों पर लाइसेंसधारी द्वारा प्रभारों के भुगतान के अधीन टीएनईबी द्वारा लाइसेंसदाता को यथा उपलब्ध करवाई गई लगभग 1800 केवीए की सीमा तक बिजली आपूर्ति। बिजली के लिए टेक ऑफ प्वाइंट अतिरिक्त बर्थ (निकट 6वें बर्थ) पर उप केन्द्र से होगा।”

6. अनुच्छेद 6.1.8 को समझा जाये, जिस प्रयोजन के लिए, इसे नीचे संक्षिप्त रूप में दिया गया है:-

“6.1.8 बिजली और पानी आपूर्ति

लाइसेंसधारी सम्पूर्ण लाइसेंस अवधि अथवा पूर्व समाप्ति, जैसी भी स्थिति हो, के लिए लाइसेंस परिसर और/अथवा कंटेनर टर्मिनल को आपूर्ति की गई बिजली के लिए सभी प्रभारों का लाइसेंसदाता को अदायगी करने के लिए जिम्मेदार होगा। लाइसेंसधारी, अपनी लागत पर, परन्तु लाइसेंसदाता की सतुष्टि पर, बिजली के उपभोग के मापन के लिए मीटर संस्थापित करेगा। किन्हीं कारणों से अथवा योजनाबद्ध अनुरक्षण बन्द करने की स्थिति में बिजली की आपूर्ति बाधित होने अथवा खराब होने की स्थिति में, उसके परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी को होने वाले किसी नुकसान अथवा क्षति के लिए लाइसेंसदाता द्वारा किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। लाइसेंसधारी, अपनी लागत पर, लाइसेंसदाता के पूर्व लिखित अनुमोदन और लाइसेंसधारी द्वारा संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमति प्राप्त करने के अधीन बिजली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी पर प्रभार्य प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार होंगे।

लाइसेंसदाता द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है कि प्रत्येक घटना के लिए 4 घंटे से कम समय, एक वर्ष में कुल 500 घंटों से कम नहीं हो, के लिए लम्बी बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में, अनुच्छेद 7.3 और 7.3.4 के प्रावधानों के अधीन उत्पादकता में नुकसान के लिए लाइसेंसदाता द्वारा विचार किया जाएगा। तथापि, अनुच्छेद 7.3.5.2 के प्रावधान के अनुसार रॉयल्टियों के भुगतान में इस खाते पर किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लाइसेंसधारी भी तमिलनाडु सरकार/तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधन के परिणामस्वरूप बिजली प्रशुल्कों के मामले में किसी वृद्धि की अदायगी करने की सहमति और वचनबद्ध देता है।

तथापि, प्रशुल्क, करों आदि के लिए एचटी तथा एलटी उपभोक्ताओं के लिए टीएनईबी नियमों तथा विनियमों, दंडात्मक खंडों के साथ, यदि कोई हो, लाइसेंसधारी पर भी लागू होगा।

लाइसेंसदाता ने लाइसेंसधारी को अभ्यावेदन किया है कि लाइसेंसधारी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी है और लाइसेंसधारी को पानी की आपूर्ति ऑफर की है। लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता से लाइसेंसशुदा परिसर और/अथवा कंटेनर टर्मिनल के लिए लाइसेंसदाता द्वारा (समय-समय पर संशोधन और/अथवा सभी पतन उपभोक्ताओं पर यथा लागू के अधीन) निर्धारित दरों पर पानी की आपूर्ति करने के लिए सहमत है। लाइसेंसधारी इसके लिए देनदार होगा, और प्रचलित दर पर लाइसेंसशुदा परिसर और/अथवा कंटेनर टर्मिनल को उपलब्ध करवाये गए पानी के लिए सभी प्रभार सम्पूर्ण लाइसेंस अवधि अथवा शीघ्र टर्मिनेशन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए लाइसेंसदाता को अदायगी करेगा। लाइसेंसधारी, अपनी लागत पर परन्तु लाइसेंसदाता की संतुष्टि अनुसार, पानी के उपभोग के माप के लिए मीटर संस्थापित करेगा।

लाइसेंसदाता तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) से थोक में बिजली प्राप्त करता है। भविष्य में यदि टीएनईबी से बिजली पर कोई रोक अथवा आपूर्ति कम होती है तो लाइसेंसधारी को आपूर्ति की गई बिजली भी लाइसेंसधारी के कंटेनर टर्मिनल के लिए समानुपातिक रूप से इन अवरोधों/कम आपूर्ति के अधीन होंगी। लाइसेंसधारी ऐसी स्थिति में पानी के अवरोधों/कम आपूर्ति के अधीन होगा कि लाइसेंसदाता को लाइसेंसदाता के कंटेनर टर्मिनल के लिए समानुपातिक रूप से कोरंगनी से तूतीकोरिन पतन तक पानी की उसकी प्राप्ति में कोई अवरोध अथवा कम आपूर्ति पेश आती है।”

6.2 के अधीन उल्लिखित उपर्युक्त अपेक्षाओं के संबंध में, पतन ने 6.2.1(viii) के अधीन यथा उल्लिखित बिजली की आपूर्ति के लिए उपलब्ध करवाया है।

7. इसपर भी विवाद नहीं है कि बिजली उपभोग प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

8. करार के अनुसार, बिजली के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के समय बिजली आपूर्ति के लिए इसकी बाध्यता के मददेनजर पतन द्वारा आवश्यक रूप से वहन किया जाना है, प्रश्न है कि क्या बुनियादी ढांचे के अनुरक्षण के लिए पतन अनुरक्षण व्यय की पूर्ति के लिए बाध्यकारी है अथवा इसे लाइसेंसधारी से वसूल किया जा सकता है।

9. प्रश्न है कि क्या उपरिचर्चों के लिए ऐसे प्रभार 6.1.8 के अधीन वसूल किए जा सकते हैं? 6.1.8 के पहले अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि लाइसेंसधारी पर प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार होंगे। स्वीकार्य है कि, टीएनईबी ने उपरिचर्च प्रभारों के संबंध में कोई अनुसूचित दरें निर्धारित नहीं की हैं और इसलिए जब तक उपरिचर्च प्रभारों के लिए टीएनईबी द्वारा विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की जाती है तो उपरिचर्च व्यय की वसूली के लिए 6.1.8 के अधीन प्रावधान इनवोक नहीं किए जा सकते।

10. तथापि, मेरी राय में, उक्त प्रभार संभवतः 6.2.3 में देखे जा सकते हैं। 6.2.3 के अनुच्छेद 2 में निम्नवत् कहा गया है:-

“लाइसेंसधारी लाइसेंस अवार्ड किए जाने की तारीख से इसकी समाप्ति अथवा खत्म किए जाने तक, जैसी भी स्थिति हो, लाइसेंसशुदा परिसर और/अथवा कंटेनर टर्मिनल को हर समय अच्छी स्थिति में बनाये रखने के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा।

लाइसेंसधारी, लाइसेंस अवधि के दौरान हर समय, अपने स्वयं के जोखिमों, लागतों, प्रभारों तथा व्ययों पर, लाइसेंसशुदा परिसर और/अथवा कंटेनर टर्मिनल अथवा उसके किसी हिस्से में अनुरक्षण मरम्मत, नवीकरण और परिवर्तित किए जाने का कार्य निष्पादित करेगा और अदायगी करेगा, भले ही इस्तेमाल और परिचालनों अथवा माल के डेटोरेशन के कारण ऐसा हुआ हो, ताकि इस लाइसेंस की समाप्ति अथवा खत्म किए जाने पर, यह, सिवाय सामान्य टूट-फूट के, अच्छी स्थिति में हो जैसा लाइसेंस की शुरुआत में था।

लाइसेंसधारी निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार मुख्य कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों को नए कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों से बदले जाने के लिए सहमत है और वचन देता है जोकि पहले वाले उपस्करों से किसी भी प्रकार से कम नहीं होंगे:

1) परिसंपत्तियों की मौजूदगी की तारीख से 17वें से 20वें वर्ष के बीच रेल माउटेड घाट क्रेनों का बदलना।

2) परिसंपत्तियों की मौजूदगी की तारीख से 17वें से 20वें वर्ष के बीच रबड़ टायर वाली गैट्री क्रेनों का बदलना।

इस करार के अधीन उपस्कर बदलने के प्रयोजन के लिए, बदले जाने वाली परिसंपत्तियों की मौजूदगी की तारीख अनुच्छेद 5.12 के अनुसार होगी।

लाइसेंसधारी उपस्करों को बदले जाने की देय तारीख से काफी पहले उपस्करों को बदलने की योजना से सहमत है।

इसके अधीन कि इस करार में क्या दिया गया है, लाइसेंसधारी लाइसेंस अवधि के बाद सुविधाओं तथा ढांचों के रखरखाव, अनुरक्षण अथवा बदलने के लिए अदायगी अथवा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं है।

[कानूनी राय के पैरा 10 में दिया गया संदर्भ एलए का खंड सं. 6.2.3 है। तथापि, एलए में, खंड सं. 6.3 है जिसमें उपर्युक्त विनिर्दिष्टन है और कानूनी राय में उल्लिखित 6.2.3 नहीं है।]

जब बिजली उपलब्ध करवाना पत्तन की जिम्मेदारी है, उन लाइनों के अनुरक्षण के समय प्रोद्भूत कोई प्रभार आवश्यक रूप से लाइसेंसधारी द्वारा ही वहन किया जाएगा क्योंकि पत्तन द्वारा ऐसे व्ययों के भुगतान के लिए करार में नहीं दिया गया है।

11. यदि तारें लाइसेंसधुदा क्षेत्र से बाहर स्थित होती हैं, चूंकि बिजली लाइन विभिन्न बर्थों के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु उपयोग की जाती है, उक्त बुनियादी ढांचे के अनुरक्षण के लिए पत्तन द्वारा प्रोद्भूत व्यय आवश्यक रूप से लाभार्थियों के बीच बांटे जाएंगे।

12. यह दिखाई देता है कि पत्तन न्यास ने उपरिव्यय प्रभारित करने के लिए अनुमति मांगने हेतु टीएनईबी को लिखा था और टीएनईबी ने ट्रांसफार्मर हानि, एमडी प्रभारों आदि के रूप में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए न लाभ न हानि आधार पर गणना करने के लिए पत्तन न्यास को अनुमति दी थी।

13. इन परिस्थितियों में, मेरी राय है कि चूंकि सुविधा का अनुरक्षण लाइसेंस करार के उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए लाइसेंसधारी पत्तन को अनुरक्षण प्रभारों (समानुपातिक रूप से) की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है और यह इसे संग्रहित करने के पत्तन के अधिकार के भीतर है।”

9.2. वीओसीपीटी ने, एएसजी की कानूनी राय की प्रति अग्रेषित करते समय, निम्नलिखित उल्लेख किया था:

(i). एएसजी ने राय व्यक्त की है कि लाइसेंस करार के 6.1.8 का प्रथम अनुच्छेद लाइसेंसधारी पर वसूल किए गए प्रभारों के लिए है और तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीईएनबी) की अनुसूचित दरों के अनुसार होगा। स्वीकार्य है कि टीएनईबी ने उपरिव्यय प्रभारों के संबंध में कोई अनुसूचित दरें निर्धारित नहीं की हैं। अतः जब तक उपरिव्यय प्रभारों के लिए टीएनईबी द्वारा विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक 6.1.8 के अधीन प्रावधानों को उपरिव्यय व्यय की वसूली करने के लिए इनबोक नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण लंबित मुद्दे का समाधान करने के लिए उपयुक्त निर्णय ले सकता है।

(ii). अन्य खंड 6.2.3 इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं है और ऐसी वसूली के लिए नहीं आ सकता।

10. उपर्युक्त पैरा 8 (ii) में दी गई संयुक्त सुनवाई के दूसरे कार्यवाई बिन्दु के संदर्भ में, वीओसीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 14 फरवरी 2018 द्वारा कहा है कि लागत विश्लेषण के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2016 द्वारा अनुमोदित दरमान के संशोधन के अनुसार, प्रस्तावित प्रशुल्क का अनुमोदन पत्तन द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिव्यय व्ययों की वसूली के लिए प्रभारों सहित विभिन्न सेवाओं के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं के आधार पर प्रशुल्क नीति दिशानिर्देश, 2015 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सुविचारित किया गया था। इसके अलावा, पीएसएसिकाल सहित विभिन्न उपयोक्ताओं के लिए सिर्फ बिजली के वितरण की सुविधा के लिए शामिल प्रासंगिक लागत का पृथक्करण और प्रभाजन बहुत ही क्यूबेरसम है क्योंकि विभिन्न गतिविधियां आउटसोर्स की जाती हैं और इसलिए केवल प्रतिशत आधार पर प्रभाजित किया गया है। इसलिए, वीओसीपीटी ने अनुरोध किया है कि ऐसा लागत विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता और विषयक मुद्दे पर श्री जी. राजा गोपालन, एएसजीआई से प्राप्त कानूनी राय के आधार पर उपयुक्त निर्णय लेने का अनुरोध किया है।

11. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग-से भेजा जाएगा। ये व्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

12. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समय सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

(i). वीओसीपीटी का प्रस्ताव दिनांक 5 सितम्बर 2017 पीएसएसिकाल टर्मिनल्स लि. (पीएसएसिकाल) से बिजली उपरिव्यय प्रभारों की वसूली के लिए पत्तन को मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा दिए गए सुझाव पर अपने विधि प्रकोष्ठ से पत्तन द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय के आधार पर पीएसएसिकाल टर्मिनल्स लि. (पीएसएसिकाल) द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिव्यय व्ययों की वसूली के लिए इस प्राधिकरण के अनुमोदन की मांग करता है, अन्य उपयोक्ताओं के समान है।

(ii). इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी दिनांक 4 मई 2004 और आदेश सं. टीएमपी/22/2006-टीपीटी दिनांक 14 जुलाई 2008 में वीओसीपीटी द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2004 को दी गई कानूनी राय के आधार पर पत्तन उपयोक्ताओं, संविदाकारों और पीएसएसिकाल से पत्तन द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिव्यय व्ययों की वसूली के लिए लेवी के निर्धारण हेतु वीओसीपीटी द्वारा पहले दाखिल किए गए प्रस्तावों का निपटान करते समय इस मुद्दे पर कार्य किया था। पीएसएसिकाल और वीओसीपीटी के बीच हुए विशिष्ट बीओटी लाइसेंस करार (एलए) दिनांक 15 जुलाई 1998 द्वारा पीएसएसिकाल और वीओसीपीटी शासित किए जाते हैं।

(iii). जैसाकि पूर्व अनुच्छेदों में पहले ही बताया गया है, पत्तन द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के मामले में उपरिव्यय प्रभारों की वसूली करने के लिए लेवी के निर्धारण हेतु पत्तन के प्रस्ताव के संदर्भ में आदेश सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी दिनांक 4 मई 2004 के पैरा 6.2 में बताया गया है कानूनी सलाहकार श्री बी. भारत भूषण से पत्तन द्वारा यथा प्राप्त वीओसीपीटी द्वारा दी गई कानूनी राय दिनांक 9 फरवरी 2004 का प्रासंगिक हिस्सा निम्नवत् है:-

”जहां तक अन्य पत्तन उपयोक्ताओं के साथ करार का संबंध है, जोकि प्रीडोमिनेन्टली एकसमान हैं, मैंने पाया है कि खंड (ii) आपके बचाव में आएगा। यह खंड विनिर्दिष्ट करता है कि लाइसेंसधारी, पट्टा की अवधि के दौरान, सभी दरें, कर और प्रत्येक विवरण के प्रभार अब देय अथवा इसके

बाद डिमांडस किए गए प्लॉट अथवा उसपर निर्मित किए जाने वाले भवनों के मामले में पट्टादाता अथवा पट्टाधारी द्वारा देय हो जाता है। इस प्रावधान का यह अर्थ होगा कि संशोधित की गई कोई दरें, कर अथवा प्रभार, संशोधित किए जा रहे अथवा संशोधित किए जाने वाले भी पट्टाधारी द्वारा भुगतान किए जाएंगे।”

“करार में इस कॉलम विशेष में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि लाइसेंसों पर प्रभारित ‘प्रभार’ टीएनईबी की अनुसूची दरों के अनुसार होंगे। अतः मेरी राय में मैं पीएसए सिकाल लि. अतिरिक्त संग्रहण के किसी प्रयास के मामले में अपने अधिकारों की निश्चित रूप से रक्षा कर सकता है और खंड 6.1.8 में करार में स्वीकृत से इतर कोई अतिरिक्त अदायगी नहीं करनी होगी।”

“मैं सुझाव दूंगा कि यह प्रस्ताव मैं पीएसए सिकाल लि. के सिवाय जोकि आपके साथ उनके करार द्वारा संरक्षित है, सभी उपयोक्ताओं पर समानुपातिक वृद्धि के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। वृद्धि के प्रतिशत के बारे में बात करते हुए, मेरा अनुमान है, यह उचित अनुपात में होना चाहिए।

- (iv). पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों और पीएसए सिकाल से बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिख्य व्ययों की वसूली करने के लिए उपभोग की गई बिजली की रु. 1.15 प्रति इकाई की लेवी के निर्धारण के लिए पत्तन के प्रस्ताव के संदर्भ में अनुवर्ती आदेश सं. टीएमपी/22/2006-टीपीटी दिनांक 14 जुलाई 2008 में, इस प्राधिकरण ने मई 2004 आदेश से संबंधित कार्यवाहियों के दौरान वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित कानूनी राय के आधार पर पीएसए सिकाल के सिवाय पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों से बिजली की आपूर्ति हेतु उपरिख्य व्ययों की वसूली के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित लेवी अनुमोदित की थी।
- (v). वीओसीपीटी ने अपने विधि प्रकोष्ठ द्वारा दी गई राय के साथ प्रस्ताव दिनांक 5 सितम्बर 2017 दाखिल किया था। एलए के अनुच्छेद 6.1.8 के संदर्भ को लेते हुए पत्तन के विधि प्रकोष्ठ द्वारा दी गई राय का सार है कि टीएनईबी की दरों की अनुसूची में उपरिख्य प्रभार भी शामिल होंगे, और, उपरिख्य प्रभारों का संग्रहण अतिरिक्त संग्रहण के रूप में नहीं माना जाएगा। तथापि, वीओसीपीटी ने बाह्य स्रोत, (अर्थात्) सरकारी विधि अधिकारी (एसजी) से कानूनी राय लेने के मामले की कार्यवाहियों के दौरान निर्णय लिया था। एसजी द्वारा दी गई राय वीओसीपीटी के विधि प्रकोष्ठ द्वारा दी गई राय का समर्थन नहीं करती है। जैसाकि एसजी द्वारा राय दी गई है, लाइसेंसधारी पर प्रभारित प्रभार एलए के अनुच्छेद 6.1.8 में यथा उल्लिखित टीएनईबी की दरों की अनुसूची के अनुसार होंगे। परन्तु टीएनईबी ने उपरिख्य प्रभारों के संबंध में कोई अनुसूचित दरें निर्धारित नहीं की हैं। अतः, एसजी ने राय व्यक्त की है कि जब कि उपरिख्य प्रभारों के लिए टीएनईबी द्वारा विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की जाती है तब तक उपरिख्य प्रभारों की वसूली के लिए अनुच्छेद 6.1.8 को शामिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, एसजी की राय ने वीओसीपीटी के विधि प्रकोष्ठ द्वारा दी गई राय को अधिक्रमित किया है। वीओसीपीटी ने भी एसजी द्वारा दी गई राय पर विचार किया है और इस प्राधिकरण से मामले का समाधान करने के लिए उपयुक्त निर्णय करने का अनुरोध किया है। वीओसीपीटी ने अपने विधि प्रकोष्ठ द्वारा दी गई पूर्व राय को नहीं दोहराया है। ऐसी स्थिति में, इस प्राधिकरण द्वारा एसजी द्वारा दी गई राय पर विचार किया है जैसाकि वीओसीपीटी द्वारा सुझाव दिया गया है।
- (vi). एलए का अनुच्छेद 6.3 सुविधाओं के अनुरक्षण तथा बदलने के लिए पीएसएसिकाल की जिम्मेदारी को शासित करता है। इस अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए, एसजी की राय है कि पीएसएसिकाल पत्तन को अनुरक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है और यह इसे संग्रहीत करने के लिए वीओसीपीटी के अधिकार के भीतर है क्योंकि सुविधा का अनुरक्षण एलए के उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तथापि, वीओसीपीटी का मत है कि अनुच्छेद 6.3 इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं है। चूंकि वीओसीपीटी इस राय से सहमत नहीं है, इसलिए एसजी की यह राय इस प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।

13. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, पीएसए सिकाल टर्मिनल्स लि. पर आदेश सं. टीएमपी/29/2016-वीओसीपीटी दिनांक 17 सितम्बर 2016 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बिजली प्रभारों पर उपरिख्य प्रभारों की वसूली के लिए लेवी को शासित करने वाले अध्याय V की मौजूदा अनुसूची 5.21 लागू करने के लिए वीओसीपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असा./33/18]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 27th March, 2018

**No. TAMP/73/2017-VOCPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the V.O. Chidambaranar Port Trust for recovery of Overhead Charges on Electricity Charges for electricity consumed by M/s.PSA SICAL Terminal Ltd. as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports****Case No. TAMP/73/2017-VOCPT**

V.O. Chidambaranar Port Trust

-----

Applicant

**QUORUM**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**(Passed on this 19<sup>th</sup> day of March 2018)

This case relates to the proposal dated 05 September 2017 received from V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) regarding recovery of overhead charges on Electricity Charges for electricity consumed by M/s.PSA SICAL Terminals Ltd. (PSASICAL)

2.1. The points made by VOCPT in its letter dated 05 September 2017 are summarised below:

- (i). The VOCPT had earlier proposed for the recovery of overhead charges in respect of supply of electricity to Port users, contractors and in respect of PSASICAL to levy overhead charges @ ₹1.15/ unit.

However, the Authority approved the rate of ₹1.15 per unit of electricity vide Order No.TAMP/22/2006-TPT dated 14 July 2008 to recover overhead expenses for supply of electricity from Port users/ contractors excluding PSASICAL. The Authority did not approve Port's proposal to recover the said charges @ ₹1.15 unit from PSASICAL for usage of electricity in VII Berth Container Terminal citing lack of explicit confirmation authorized by the Agreement with the Operator.

- (ii). In this regard, considering Port's Vigilance suggestion to take up the issue of collection of overhead charges once again to TAMP to make the applicability of overhead charges to M/s.PSA SICAL also, a legal opinion has been obtained from Port's Legal cell. A copy of legal opinion obtained on 03 August 2017 is furnished by VOCPT which is brought out here for ease of reference:

*"Whether as per Clause 6.1.8 of License Agreement the Port Trust is entitled to collect overhead charges from M/s.PSA SICAL Terminal Ltd. is the question to be decided in this case. Clause 6.1.8 of the license Agreement deals with power and water supply and collection of charges for the powers supplied to the licensed premises of M/s.PSA SICAL Terminals Ltd.*

*As per the above clause the power charges levied on the licensee shall be as per the scheduled rates of TNEB. The contention of the Finance and Mech Elect Engg Department is that overhead charges are levied from all port users/ Contractors including Private Terminal Operators in the Port as per the agreements entered with them. Since there is no provision in the License Agreement made with M/s.PSA SICAL Terminals Ltd., regarding collection of overhead charges Port is not authorised to collect overhead- charges from them.*

*In the general revision Order dated 11 December 2011 the existing tariff prescribed at ₹ 1.15 per unit of electricity consumed to recover the overhead expenses for supply of electricity from port to users / contractors was retained in the revised SOR. The TNEB communication which conveyed no objection to Port for collecting overhead charges from the lessee to meet additional expenditure in terms of transformer loss, MD charges etc. stated that in so far as the overhead charges are collected duly complying with the provisions of 31.03 (1) of the Terms and conditions of the TNEB i.e. collection made on 'no profit no loss basis'. As per the Clause 6.1.8. of the License Agreement the Port is entitled to levy charges from the licensee as per the schedule rates of TNEB. As such the schedule rates of TNEB would include overhead charges also as per the provision of the 31.03(1) of the terms and conditions of the TNEB, if the collection is made on 'no profit nor loss basis'.*



*Even though there is no provision in clause 6.1.8 of the Licence agreement providing for collection of overhead charges, the words the charges levied on the Licensee shall be as per the schedule rates of TNEB would include collection of overhead charges also. This will not be considered as additional collection of charges as already stated in the earlier legal opinion."*

2.2. In view of the above, the VOCPT has requested this Authority to consider the current submission of the port to apply overhead charges to PSASICAL also with respect to existing Scale of Rates vide scale 5.21 of Chapter V.

3. The brief history of the case is given below:

- (i). The VOCPT had approached this Authority in 2003 requesting for fixing a levy to recover overhead charges in respect of electricity charges for all users, including PSASICAL.
- (ii). The VOCPT had then forwarded a copy of legal opinion obtained by it from Legal Adviser Shri. B. Bharath Booshan which is brought out in the Order passed by this Authority vide Order No.TAMP/79/2003-TPT dated 4 May 2004 at Para 6.2. During processing of this case, the PSASICAL had objected the proposed levy.
- (iii). The legal opinion given by VOCPT dated 9 February 2004 as obtained by VOCPT from Legal Adviser Shri. B. Bharath Booshan in concluding para states as follows:

*"I, therefore, would suggest that the proposal could be implemented with a proportionate hike, to all the users, except M/s. PSA SICAL Ltd., who is protected by their agreement with you. Speaking about the percentage of hike, I guess, it has to be in the reasonable ratio."*

Thus, the legal opinion then forwarded by VOCPT in 2004 categorically stated that overhead charges are applicable to all users except M/s.PSA SICAL who is protected by their agreement with VOCPT.

- (iv). This Authority vide its Order dated 4 May 2004, rejected the proposal of VOCPT for introduction of new levy to cover overhead expenses relevant to electric supply for reasons stated in the said Order.
- (v). (a). Subsequently, the VOCPT in the year 2006 submitted a proposal for fixation of a levy to recover overhead charges in respect of electricity charges. This Authority vide its Order No.TAMP/22/2006-TPT dated 14 July 2008 had, based on the proposal of VOCPT, approved levy of ₹1.15 per unit of electricity consumed by port users / contractors to recover the overhead charges in respect of supply of electricity.
- (b). As regards PSA SICAL, para 9(viii) of the 14 July 2008 Order which was based on the then legal opinion furnished by VOCPT is reproduced as below:

*"The TPT has proposed to bring the supply of electricity to PSA SICAL also within the ambit of the proposed levy. The PSA SICAL has challenged the proposed levy claiming that it has to reimburse charges based on the scheduled rates of TNEB as per the BOT Agreement.*

*Clause 6.1.8. of the BOT agreement regulates power and water supply arrangement. The relevant clause clearly specifies that that the charges levied on the licensee shall be as per the scheduled rate of the TNEB. The legal opinion obtained by TPT earlier also endorses the position maintained by PSA SICAL.*

*The TPT has, however, referred TNEB's communication which conveyed no objection to TPT collecting overhead charges, from the lessee to meet additional expenditure in terms of transformer loss, MD charges, etc., insofar as the overhead charges are collected duly complying with the provisions of 31.03 (1) of the Terms and Conditions of the TNEB i.e., collection is made on 'no profit no loss basis'. The clarification given by the TNEB generally permits TPT to levy overhead charges but it does not appear to have been given in the specific case of PSA SICAL after examining the provisions contained in the BOT Agreement.*

The TPT has not been able to explicitly confirm that it is authorised under the BOT Agreement to recover the overhead for distribution of electricity from the PSASICAL. The proposal of the TPT to levy overhead charges from PSA SICAL is, therefore, not approved.

*Incidentally, even the TPT has subsequently included the related expenditure pertaining to the PSA SCAL for estimating the surplus / deficit position in the revised cost statement prepared for general revision of its Scale of Rates pending a final decision by this Authority on its proposal to levy overhead charges on electricity in respect of PSA SICAL."*

- (vi). Subsequently, this Authority, while approving the general revision of SOR of VOCPT vide Order No.TAMP/9/2010-TPT dated 11 October 2011, has allowed the recovery of then existing levy i.e. at the rate of ₹1.15 per unit approved in the 14 July 2008 Order for supply of electricity from port users / contractor except PSASICAL as brought out in para 17(xLv) of the 11 October 2011 Order.
- (vii). While approving the subsequent general revision of SOR of VOCPT under Tariff Policy 2015, vide Order No.TAMP/29/2016-VOCPT dated 17 September 2016, this Authority has approved the recovery of overhead expenses for supply of electricity by port at ₹1.47 per unit for supply of electricity from port users / contractor except PSASICAL as proposed by VOCPT.

4.1. It is also relevant to state that the VOCPT vide its letter no.FIN/OFFCJ-SOR-GEN-IV-15-4090 dated 18/19 December 2015 requested to examine the issue based on the observation of Audit on levy of overhead charges at ₹1.15 per unit on electricity consumed by M/s.PSA SICAL Terminal Ltd. and requested to amend Authority's Order No.TAMP/9/2010-TPT dated 11 October 2011 for settlement of Audit remark.

4.2. In this regard, it was communicated to VOCPT vide our letter dated 7 January 2016 that the decision of this Authority in July 2008 Order of not approving the levy for PSA SICAL has not been reversed in the tariff Order of October 2011. Hence, the action of the VOCPT of not levying the overhead charges from the PSA SICAL is found to be in line with the Order passed by this Authority in October 2011. The VOCPT has not pointed out any apparent error on face of records considered in the said order. Hence, the question of amendment to the October 2011 Order sought by the VOCPT does not arise.

5. The VOCPT has now, citing the legal opinion of the legal cell of the VOCPT as brought out in para 2.1. above, requested this Authority to consider the current port's submission on the issue and has sought approval for collection of overhead charges from the PSASICAL also with respect to existing Scale of Rates vide scale 5.21 of Chapter V.

6. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the VOCPT proposal was circulated to M/s.PSA SICAL Terminal Ltd. and Tamil Nadu Electricity Board vide our letter dated 13 October 2017 seeking their comments. The comments received from PSASICAL was forwarded to VOCPT as feedback information. The VOCPT has not furnished any comments thereon.

7.A joint hearing in this case was held on 7 December 2017 at the VOCPT premises. The VOCPT made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the VOCPT, PSASICAL and TNEB have made their submissions.

8. As agreed at the joint hearing, the VOCPT was requested vide our letter dated 28 December 2017 with subsequent reminder dated 10 January 2018 to take action on the following points:

- (i). Vide our letter dated 13 October 2017 it was brought to the attention of VOCPT that, this Authority had passed an Order No.TAMP/79/2003-TPT dated 4 May 2004 based on the then legal opinion of Legal Adviser Shri. B. Bharath Booshan forwarded by VOCPT in 2004 vide VOCPT letter dated 25 March 2004. The legal opinion then forwarded by VOCPT which is also reproduced in para 6.2 of the Order dated 4 May 2004 stated that the proposal of VOCPT for levy of overhead charge could be implemented to all users except PSA SICAL Ltd. who is protected by their agreement with the port. Now, the VOCPT has approached this Authority based on the legal opinion given by port's legal cell. The legal opinion furnished in 2004 and legal opinion now furnished by the port from its legal cell are contradicting. Hence, the VOCPT was requested to closely examine the matter and furnish their comment

immediately. The VOCPT has stated at the joint hearing that it will obtain a legal opinion of AG in the matter. The port was requested to furnish a copy of the same to this Authority.

- (ii). The prescription of existing revised rate for recovery of overhead expenses for supply of electricity at ₹1.47/ tonne was approved by this Authority under the general revision of SOR of the port following the Tariff Policy Guidelines of 2015 issued by the Ministry of Shipping (MOS) under ARR Model. In the said Order, the rates as proposed by VOCPT for various cargo, vessel and miscellaneous services including charges for recovery of overhead expenses for supply of electricity by port were approved by this Authority.

At the joint hearing, a point arose whether the entire overhead charges for distribution of electricity including Transmission loss is being recovered by the port. As agreed at the joint hearing, the VOCPT was requested to do a cost analysis to examine whether the entire overhead charges incurred by port for distribution of electricity is recovered by the VOCPT at the existing rate of ₹1.47 per unit proposed by VOCPT in the said general revision of SOR and approved by this Authority and furnish the same to this Authority.

9.1. With reference to point of action decided at the joint hearing brought out in para 8 (i) above, the VOCPT vide its letter dated 1 February 2018 has furnished a copy of the Legal opinion dated 17 January 2018 given by the Additional Solicitor General (ASG) to VOCPT. The opinion of the ASG is reproduced below:

- "4. Article 5 of the Agreement deals with construction and clause 5.6 read as follows:-

*"5.6 Construction Power and Water*

*The Licensor shall supply power for construction purposes, as made available to the Licensor by the Tamil Nadu Electricity Board, subject to terms and conditions including payment by the Licensee, at rates prescribed by the Licensor from time to time as per provisions of Article 6.1.8."*

5. Clause 6.1 under Article 6 deals with Obligations of the Licensee and clause 6.2 deals with the obligations of the Licensor. Para 6.2.1(viii) reads as follows:-

*"6.2.1 (viii) supply power to the extent of about 1800 KVA as made available to the Licensor by TNEB subject to payment of charges by the Licensee at rates to be prescribed by the Licensor from time to time as per Article 6.1.8. Take off point for electricity shall be from the sub station at additional berth (near 6<sup>th</sup> berth)".*

6. Article 6.1.8 has to be understood, for which purpose, it is extracted here-in-under:-

*"6.1.8 Power and Water Supply*

*The Licensee shall be liable for, and shall pay to the Licensor, throughout the term of the License Period or early Termination, as the case may be, all charges for the power supplied to the Licensed Premises and/ or the Container Terminal. The Licensee shall, at its cost, but to the satisfaction of the Licensor, install metre to measure the consumption of power. In the event of disruption of power supply or break down in supply of power for any reasons whatsoever or for a planned maintenance shut down, no compensation whatsoever shall be paid by Licensor for any loss or damages caused to or suffered by the Licensee as a result thereof. The Licensee shall, at its cost, be entitled to make alternate arrangement for power subject to prior written approval of the Licensor and subject to Licensee obtaining necessary permissions from the concerned authorities. The charges levied on the Licensee shall be as per the scheduled rates of TNEB.*

*It is agreed by the Licensor that in case of prolonged power-supply disruption at a stretch not less than 4 hours for each incident, total not less than 500 hours in a Year, due consideration shall be given by the Licensor for loss in productivity under provisions of Article 7.3 and 7.3.4. However no reduction on this account shall be allowed in payment of royalties as per provision of Article 7.3.5.2.*

*The Licensee also agrees and undertakes to pay any increase in respect of power tariffs, as a result of revision by the Tamil Nadu Government / Tamil Nadu Electricity Board from time to time.*

*However the TNEB Rules and Regulations for the HT and LT consumers for Tariff, taxes etc., along with penal clauses, if any shall be applicable to the Licensee also.*

*The Licensor has represented to the Licensee that there is an adequate water supply to cater to the requirement of the Licensee and offered to supply water to the Licensee. The Licensee has agreed to take the water supply at rates fixed by the Licensor (subject to revision from time to time and as applicable to all port users) for the Licensed Premises and / or the Container Terminal from the Licensor. The Licensee shall be liable for, and shall pay to the Licensor, throughout the term of the License Period or early Termination as the case may be, all charges for the water made available to the Licensed Premises and / or the Container Terminal at the prevailing rate. The Licensee shall, at its cost but to the satisfaction of the Licensor, install meters to measure the consumption of water.*

*The Licensor receives power in bulk from Tamil Nadu Electricity Board (TNEB). In future if there are any restriction or short supply of power from TNEB, then the power supplied to the Licensee shall also be subject to these restrictions / short supply proportionately as for Container Terminal of the Licensee. The Licensee shall also be subject to restrictions / short supply of water in the event that the Licensor faces any restrictions or short supply in its receipt of water from Korangani to Tuticorin Port proportionately as for Container Terminal of the Licensor."*

In connection with the above requirements referred to under 6.2, the port has provided for supply of power as referred to under 6.2.1(viii).

7. *It is also not in dispute that electricity consumption charges are being paid by the Licensee as per the scheduled rates of TNEB.*

8. *As per the agreement, while erection of necessary infrastructure for electricity has to necessarily borne by the Port in view of its obligation to power supply, the question is whether for maintenance of infrastructure the Port is bound to meet the maintenance expenditure or it could be recovered from the Licensee.*

9. *The question is whether such charges for over-heads could be recovered under 6.1.8? The last line of the first paragraph of the 6.1.8 refers to charges levied on the Licensee shall be as per the scheduled rates of TNEB. Admittedly, TNEB has not fixed any scheduled rates with regard to over-head charges and therefore unless a specific rate is fixed by TNEB towards overhead charges, provisions under 6.1.8 cannot be invoked for recovering the over-head expenditure.*

10. *However, in my opinion, the said charges can possibly be traced to 6.2.3. Paragraph 2 onwards of 6.2.3 provides as follows:*

*"The Licensee shall be solely responsible for keeping at all times, the Licensed Premises and/ or Container Terminal in good order and condition from the Date of Award of License, till its expiry or Termination, as the case may be.*

*The Licensee shall, at all times during the License Period, at its own risks, costs, charges and expenses, perform and pay for maintenance repairs, renewals and replacements in the Licensed Premises and / or the Container Terminal or any parts thereof, whether due to use and operations or due to deterioration of materials, so that on the expiry or Termination of this License, the same shall, except, normal wear and tear, be in as good condition as at the commencement of the License.*

*The Licensee agrees and undertakes to replace the major container handling equipments by new container handling equipments having specifications not inferior to those of the equipments being replaced as per the following provisions:*

- 1). *Replacement of rail mounted quay cranes between 17<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> year from the date of existence of the assets.*

- 2). *Replacement of rubber tyred gantry cranes between 17<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> year from the date of existence of the assets.*

*For the purpose of replacement of equipment under this agreement, the date of existence of the replacement assets shall be as per article 5.12.*

*The Licensee agrees to plan for replacement of the equipments well ahead of the due date of replacement of the equipments.*

*Subject to what is provided in this Agreement, the Licensee is not required to pay for or provide for upkeep, maintenance or replacement of facilities and structures beyond the License Period.*

*[The reference given in para 10 of the legal opinion is to clause no.6.2.3 of the LA. However, in LA, the Clause no. is 6.3 which contains the above stipulation and not 6.2.3.referred in the Legal opinion.]*

While it is the responsibility of the Port to make available the electricity, any charges incurred while maintaining those lines have to be necessarily borne by the Licensee as the agreement does not provide for payment of such expenses by the Port.

11. *If the cables are located outside the licensed area, as the power line is used for supply of electricity to various berths, the expenses incurred by the Port for maintaining the said infrastructure has to be necessarily divided between the beneficiaries.*

12. *It appears that the Port Trust has written to TNEB seeking permission to charge for the overheads and TNEB has permitted the Port Trust to calculate on no-profit-no-loss basis to meet the additional expenditure in terms of transformer loss, MD charges etc.*

13. *In the circumstances, I am of the opinion that since maintenance of the facility is very much essential to achieve the objectives of the License Agreement, the Licensee is bound to reimburse to the Port the maintenance charges (proportionately) and it well within the right of the Port to collect the same."*

9.2. The VOCPT, while forwarding a copy of the Legal Opinion of ASG, has stated the following:

- (i). The ASG opined that the first paragraph of the 6.1.8 of the licence agreement refers to charges levied on the Licensee and shall be as per the scheduled rates of Tamilnadu Electricity Board (TNEB). Admittedly, TNEB has not fixed any scheduled rates with regard to overhead charges. Therefore unless a specific rate is fixed by TNEB towards overhead charges, provisions under 6.1.8 cannot be invoked for recovering the overhead expenditure. In view of the above the Authority may take appropriate decision to resolve the pending issue.
- (ii). The other clause 6.2.3. is not relevant to the purpose and may not come for such recovery.

10. With reference to the second point of action of the joint hearing brought out in para 8 (ii) above, the VOCPT, vide its e-mail dated 14 February 2018, has stated that as regards to cost analysis, as per the revision of SOR approved by the Authority vide Order dated 17 September 2016, the approval of proposed tariff was considered by the Authority as per the Tariff Policy Guidelines, 2015 based on the Annual Revenue Requirements for various services including charges for recovery of overhead expenses for supply of electricity by Port. Moreover, segregation and apportionment of the relevant cost involved exclusively for the facility of distribution of electricity for the various users including PSASICAL, is quite cumbersome because various activities are outsourced and hence could be apportioned on percentage basis only. Hence, the VOCPT has requested that the submission of such cost analysis may not be insisted and has requested to take an appropriate decision based on the legal opinion obtained from Shri G. Raja Gopalan, ASGI on the subject issue.

11. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

12. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal of the VOCPT dated 5 September 2017 seeks approval of this Authority for recovery of overhead expenses for supply of electricity by the port to PSA SICAL Terminals Ltd. (PSA SICAL) based on legal opinion obtained by the port from its legal cell flowing from a suggestion made by the Chief Vigilance Officer (CVO) to the port to recover the Electricity Overhead Charges from PSA SICAL Terminals Ltd. (PSA SICAL) also similar to other users.
- (ii). This Authority had dealt with this issue while disposing of the proposals earlier filed by the VOCPT for fixation of levy for recovery of overhead expenses for supply of electricity by the port from port users, contractors and PSASICAL based on the legal opinion given by VOCPT dated 9 February 2004 in the Order No.TAMP/79/2003-TPT dated 4 May 2004 and Order No.TAMP/22/2006-TPT dated 14 July 2008. The PSA SICAL and VOCPT are governed by a specific BOT License Agreement (LA) dated 15 July 1998 entered into between the VOCPT and the PSA SICAL.
- (iii). As has already brought out in the earlier paragraphs, the relevant portion of legal opinion dated 9 February 2004 given by VOCPT as obtained by the port from Legal Adviser Shri. B. Bharath Booshan brought out in para 6.2. of Order No.TAMP/79/2003-TPT dated 4 May 2004 with reference to the proposal of the port for fixation of levy to recover overhead charges in respect of electricity supplied by the port is as follows:

*"As far as the agreement entered in to with other port users, which are predominantly uniform, I find that clause (ii) would come into your rescue. This clause specifies that the licensee shall, during the period of lease pay all rates, taxes and charges of every description now payable or hereafter becomes payable by the lesser or lessee in respect of the demised plot of plot or the buildings to be erected thereupon. This provision would mean that any rates, taxes or charges revised, being revised or to be revised shall also be paid by the lessee."*

*"In this particular column in the agreement, it is specifically mentioned that the 'charges' levied on the licenses shall be as per the schedule rates of TNEB. Therefore in my opinion M/S PSA SICAL Ltd. can definitely vindicate their rights in case of any attempt for additional collection and not to pay anything extra other than what is granted in the agreement in the clause 6.1.8."*

*"I would suggest that the proposal could be implemented with a proportionate hike, to all the users, except M/S PSA SICAL Ltd, who is protected by their agreement with you. Speaking about the percentage of hike, I guess, it has to be in the reasonable ratio"*

- (iv). In the subsequent Order No.TAMP/22/2006-TPT dated 14 July 2008 with reference to the proposal of the port for fixation of levy of ₹1.15 per unit of electricity consumed to recover overhead expenses for supply of electricity from port users/ contractors and PSA SICAL, this Authority had approved the levy proposed by the VOCPT for recovery of overhead expenses for supply of electricity from port users/ contractors except PSA SICAL based on the legal opinion furnished by VOCPT during the proceedings relating to May 2004 Order.
- (v). The VOCPT has filed the proposal dated 5 September 2017 with the opinion given by its legal cell. The gist of the opinion given by the legal cell of the port drawing reference to Article 6.1.8 of the LA is that the Schedule of Rates of TNEB would include overhead charge also; and, collection of overhead charges will not be considered as additional collection. However, the VOCPT decided during the proceedings of this case to take legal opinion from external source, (i.e.) from the Government Law Officer (ASG). The opinion given by the ASG does not support the opinion given by the legal cell of the VOCPT. As opined by the ASG, the charges levied on the licensee shall be as per the Schedule of Rates of TNEB as referred in Article 6.1.8 of the LA. But, TNEB has not fixed any Scheduled Rates with regard to overhead charges. Therefore, the ASG has opined that unless a specific rate is fixed by TNEB towards overhead charges, provision under Article 6.1.8 cannot be involved to recover the overhead charges. Thus, the opinion of the ASG has overruled the opinion given by the legal cell of the VOCPT. The VOCPT has also considered the opinion given by the ASG and has requested this Authority to take an appropriate decision to resolve the matter. The VOCPT has not reiterated the opinion earlier given by its legal cell. That being so, the opinion given by the ASG is taken into consideration by this Authority as suggested by the VOCPT.

- (vi). Article 6.3 of the LA governs the responsibility of the PSASICAL for maintenance and replacement of facilities. Referring to this Article, the ASG is of the opinion that the PSASICAL is bound to reimburse to the port the maintenance charges and it is well within the right of VOCPT to collect the same since maintenance of the facility is very much essential to achieve the objectives of LA. However, the VOCPT is of the view that Article 6.3 is not relevant for the purpose. Since the VOCPT does not agree with this opinion, this opinion of the ASG does not fall in the zone of consideration by this Authority.

13. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the proposal of the VOCPT to apply the existing schedule 5.21 of Chapter V governing levy for recovery of overhead charges on Electricity Charges approved by this Authority vide Order No.TAMP/29/2016-VOCPT dated 17 September 2016 on PSA SICAL Terminals Ltd is not approved.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./33/18]